

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1944-सितम्बर 22, 2022 <i>Bhadra 31, Thursday, Saka 1944- September 22, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2022

जी.एस.आर.55.— राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 07-07-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 7, 2022

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 62 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 63 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

63.	नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को किराये पर लेना जैसे कि स्ट्रेटेजिक आईटी सलाहकार सेवाएं, वित्तीय सलाहकार सेवाओं को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन सलाहकार और प्रबंध परामर्शी सेवाएं, कार्यक्रम और परियोजना प्रबंध, परियोजना प्रबंध इकाइयों की स्थापना को सम्मिलित करते हुए क्षमता विकास, कार्यक्रम प्रबंध इकाइयों को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम/परियोजना को मानिटर करना, समन्वय इत्यादि, प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता निर्धारण को सम्मिलित करते हुए क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंध, कन्टेन्ट विकास, थीम आधारित/कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण, परियोजना प्रबंध प्रमाणीकरण कार्यक्रम, जनशक्ति संवर्धन, गुण अर्जन, संव्यवहार सलाहकार सेवाएं, सोशल मीडिया सलाहकार, समर्थन पुनर्विलोकन, नीतियों की तैयारी और क्रियान्वयन।	नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट	दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार वित्त विभाग की सहमति से नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।
-----	--	---	--

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.